

श्री एम.पी.ए. समद समदानी (केरल): सर, मैं स्वयं को इससे संबद्ध करता हूँ।

श्री सभापति: मैं बीच में इंटरवीन कर रहा हूँ, माननीय सदस्य इसे गंभीरता से सुनें। अभी हरेन्द्र सिंह मलिक के नाम से एक स्पेशल मेशन था जो इन्होंने पढ़कर सुनाया लेकिन इनके नाम से एक क्वेश्चन भी था जिसे इनकी अनुपस्थिति के कारण पोस्टपोन करना पड़ा। मैं चाहूंगा कि आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए उस क्वेश्चन को पढ़कर सुना दूँ। वित्त और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि कंपनी कार्य विभाग ने सीमिन जांच प्रतिवेदन के निष्कर्ष के आधार पर स्थानीय निदेशक, डी.सी.ए., पश्चिमी क्षेत्र को यह निदेश दिया है वह कंपनी रजिस्ट्रार द्वारा रिलायंस इंडस्ट्रीज के आवश्यक कारण बताओ नोटिस जारी करने और अन्य कार्रवाई करने तथा कंपनी अधिनियम की धारा 372 क (2) के उल्लंघन के लिए अभियोजन कार्रवाई आरंभ करने की सलाह दे। यदि हाँ तो क्षेत्रीय निदेशक, डी.सी.ए., पश्चिमी क्षेत्र और कंपनी रजिस्ट्रार द्वारा की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है? यदि कोई कार्रवाई नहीं की गई है, तो उसका ब्यौरा क्या है?

श्री हरेन्द्र सिंह मलिक (हरियाणा): सभापति जी, यदि आपकी अनुमति हो तो मैं कुछ अर्ज करूँ।

श्री सभापति: जब दूसरा नम्बर आएगा, तब बताइएगा।

श्री हरेन्द्र सिंह मलिक: सभापति जी, बात ऐसी है कि दो या तीन सवाल लिए जाते थे। मेरा नम्बर सातवें सवाल पर था। मैंने माननीय लघु उद्योग मंत्री से समय मांगा था तो उन्होंने मुझे 11:30 बजे का समय दिया था और मुझे समय 12:05 पर मिल पाया। इसीलिए मैं रह गया।

श्री सभापति: कोई बात नहीं है।

श्री हरेन्द्र सिंह मलिक: इसे स्थगित कर दीजिए और अगले में ले लें।

श्री सभापति: ठीक है।

Grievances of students in Delhi

SHRI B.P. APTE (Maharashtra): Sir, About one lakh students from all parts of the country assembled in Delhi to place their demands before the Central Government. The rally organised by the country's premier students organisation, the Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad, presented a charter to the Prime Minister, signed by fifteen lakh students. The students do appreciate the steps being taken for Sarva Shiksha and for making education Indo-centric. They also appreciate the steps towards

curing the curricula of Marxist philosophy. However, the students are greatly disturbed by commercialisation of education and the spectre of unemployment. Some of their pressing demands include the need to spend at least 6 per cent of the GDP on education. It is also necessary to take certain steps immediately, like (1) Appointment of a task force for suggesting concrete steps for curbing commercialisation of education and to rationalise the fee structure. (2) Establishment of an Education Development Bank to help students and institutions. (3) Linking of the quantum of scholarship, particularly, in the case of SC and ST students, be linked with the price index. (4) Private participation in educational development be both encouraged and regulated by incentives like tax benefits and by norms discouraging commercialisation. (5) Correlate educational planning with development planning and conduct a national survey of manpower requirement, for its proper management and for the benefit of the country's economy. (6) Active steps, including resorting to Central legislations, if felt necessary, be taken to ensure university autonomy, and, at the same time, to regulate deemed universities. (7) Higher education curricula be so designed as to include mandatory social services for six months, and a minimum training in military discipline, to inculcate the spirit of nationalism and dedication.

श्री भारतेन्दु प्रकाश सिंहल (उत्तर प्रदेश): मैं अपने को इससे सम्बद्ध करता हूँ।

SHRI BALBIR K. PUNJ (Uttar Pradesh): I associate myself with the sentiments expressed by Shri B.P. Apte.

Problem of Fluoride in drinking water in Maharashtra

श्री सतीश प्रधान (महाराष्ट्र): सभापति महोदय, हमारी भारतीय संस्कृति सारी दुनिया से अलग है। हमारे पूर्वजों ने हमें सिखाया है कि यदि रास्ते से चल रहा मुसाफिर घर के सामने रुक कर पीने के लिए पानी मांगे तो हम उसे अंदर बुला कर बैठने के लिए कह कर उसे पहले गुड़ दे कर पानी दें। हमारी संस्कृति में पीने के लिए पानी देना सर्वोच्च प्राथमिक बात मानी जाती है। लेकिन आज महाराष्ट्र के यवतमाल जिले के 470 गांवों में से 918 के जल स्रोत की जांच करने के बाद पता चला कि ये सभी फ्लोराइड की वजह से दूषित हैं। यह दो साल पहले पता चला। फिर भी आज तक महाराष्ट्र सरकार ने अभी तक कुछ भी उपाय नहीं किया है। सिर्फ यहां पर एक सूचना फलक लगाया—“यह पानी पीने लायक नहीं है”। इन गांवों में पर्याप्त पीने के पानी की व्यवस्था न होने के कारण लोग इसी पानी को पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं और आज भी वही कर रहे हैं। परिणामस्वरूप